Minister urges industry to back farmer producer organisations

OUR BUREAU

New Delhi, September 27

The government has sought the participation of the private sector in supporting farmer producer organisations (FPOs) and linking them with market, Agriculture Minister Radha Mohan Singh said on Thursday.

"While many State governments and even the private sector is supporting FPOs, we need to expedite these efforts. We recently called a meeting for the same in the ministry, which was attended by top private players including Haldiram's and ITC," Singh said while participating in an Assocham event.

The National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard) is already supporting over 4,000 FPOs across the country.

Farmers cannot get adequate price for their produce without value addition and focusing on value addition, processing, end-to-end management, input and output management, and marketing would go a long way in realising the government's commitment to increasing farmers' income, he remarked. Uday Kumar Varma, Assocham Secretary-General, in his speech said food value chains can be more effective when enterprises involved in value chain can agree on a set of mission values like farm viability, farm-land preservation, access to healthy food along with sustainable production practices and set of shared operational values such as accountability, long-term commitment, open and on-going communication and transparency, and use them as a means to differentiate and add value to the products they are offering to their customers/consumers.

Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh

Business Standard Page 5 28 September, 2018

Farmers at least know of agri schemes, if not my name: Minister

Agriculture Minister Radha Mohan Singh said on Thursday farmers across the country are at least aware of agricultural schemes in the current government, if not his name. He said the situation was not so during the previous regime. Attacking the previous government for neglecting the farming community, Singh said the NDA government on the other hand has given top priority to welfare of farmers, and therefore raised substantially the budget allocation to ₹2,110 billion in the last four years. PTI

Financial Express Page 12 28 September, 2018

AGRI BUDGET

Radha Mohan Singh, agriculture minister

The budget allocated by the previous government for the agriculture sector was only ₹1,21,000 crore for five years. Whereas, our government has allocated ₹2,11,000 crore in last four years alone

किसानों की आय बढ़ाने को खाद्य प्रसंस्करण जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने से किसानों को माली हालत में सुधार होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकसित होने से जहां प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे, वहीं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे। सिंह बृहस्पतिवार को यहां एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'एग्रीकल्चर फूड व वैल्यू चेन से फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।' यह किसानों की आमदनी को खुशहाल बनाने की दिशा में कारगर पहल साबित हुई है।

आम बजट में टमाटर, आलू और प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली उपजों को संरक्षित करने और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन सब्जियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की समस्या को सुलझाने के लिहाज 'आपरेशन ग्रीन' नामक योजना शुरू की गई है। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। कृषि मंत्री सिंह ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह योजना

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह

उनकी विशेष सोच से तैयार की गई है।

खाद्यान्न के मामले में भारत को निर्यातक देश बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इसमें किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका अहम है। देश में दूध का उत्पादन 16.5 करोड़ टन हो गया है। जबकि खाद्यान्न की पैदावार 28.5 करोड़ टन हो गई है। इन उत्पादों की घरेलू मांग मौजूदा आपूर्ति के मुकाबले कम है। इनका निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने 585 मंडियों को ई-नाम पोर्टल के साथ पहले ही जोड़ दिया है, जिसका लाभ किसानों को प्राप्त होने लगा है। इन मंडियों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने अगले दो वर्षों के भीतर 415 अतिरिक्त मंडियों को ई-नाम से जोड़ने की योजना तैयार की है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं।

ई-नाम से जुड़ेंगी और मंडियां

■ सूची में शामिल हो चुकी 585 मंडियां ■ 415 और मंडियां इसमें होंगी शामिल

■ नई दिल्ली (वार्ता)।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए अब तक 585 मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ दिया गया है। अगले दो साल में 415 अन्य मंडियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

सिंह ने यहां एसोचैम की ओर आयोजित कृषि संबंधित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ई-नाम योजना से जुड़ी मंडियों ने बिचौलियों के तंत्र को ध्वस्त कर दिया है और किसान अब अपने फसलों का बेहतर मूल्य पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग में आने वाले आलू, प्याज और टमाटर के मूल्य में उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से आपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई है। इस योजना से फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों को मदद मिलेगी तथा प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकेगा।

■ इस व्यवस्था से मंडियों में बिचौलियों का तंत्र हुआ ध्वस्त
■ किसानों को अब मिल रहा फसल का बेहतर मूल्य
■ मूल्यों में उतार-चढ़ाव से बचने को आपरेशन ग्रीन योजना
■ जैविक मूल्य संवर्द्धन योजना के लिए ₹400 करोड़

उन्होंने कहा कि समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य संवर्द्धन श्रृंखला मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की है जिससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार केसाथ कृषि उत्पादों और समुद्री उत्पादों का भी प्रसंस्करण किया जा सकेगा।

सिंह ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन श्रृंखला कार्यक्रम को स्थानीय, क्षेत्रीय,राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धित श्रृंखला का विकास किया गया है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कृषि योजनाओं से अंजान नहीं हैं किसान

■ नई दिल्ली (भाषा)।

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों को भले ही उनका नाम नहीं मालूम हो पर उन्हें पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी जरूर है।

सिंह ने कृषक समुदाय को नजरंदाज करने के लिए पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने किसानों के कल्याण को शीर्ष प्राथमिकता दी है। इस सरकार ने पिछले चार साल में कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है।

सिंह ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा, 'पिछली सरकार के पांच साल में कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 1.21 लाख करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने चार ही साल में 2.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।' उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को राज्य सरकारों के साथ मिलकर अधिक जोर-शोर से क्रियान्वित किया जा रहा है।

Dainik Jagran (National Edition) Page 10 28 September, 2018

किसानों की आय बढ़ाने को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देश में खाद्यान्न व दूध उत्पादन नई ऊंचाइयों पर : कृषि मंत्री
- ऑपरेशन ग्रीन से आलू, प्याज व टमाटर की खेती को मिला बल

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने से किसानों को माली हालत में सुधार होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकसित होने से जहां प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे, वहीं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे। सिंह बृहस्पतिवार को यहां एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'एग्रीकल्चर फूड व वैल्यू चेन से फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।' यह किसानों की आमदनी को खुशहाल बनाने की दिशा में कारगर पहल साबित हुई है।

आम बजट में टमाटर, आलू और प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली उपजों को संरक्षित करने और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन सब्जियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की समस्या को सुलझाने के लिहाज 'आपरेशन ग्रीन' नामक योजना शुरू की गई है। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। कृषि मंत्री सिंह ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह योजना उनकी विशेष सोच से तैयार की गई है।

खाद्यान्न के मामले में भारत को निर्यातक देश बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इसमें किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका अहम है। देश में दूध का उत्पादन 16.5 करोड़ टन हो गया है। जबकि खाद्यान्न की पैदावार 28.5 करोड़ टन हो गई है। इन उत्पादों की घरेलू मांग मौजूदा आपूर्ति के मुकाबले कम है। इनका निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने 585 मंडियों को ई-नाम पोर्टल के साथ पहले ही जोड़ दिया है, जिसका लाभ किसानों को प्राप्त होने लगा है। इन मंडियों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने अगले दो सालों के भीतर 415 अतिरिक्त मंडियों को ई-नाम से जोड़ने की योजना तैयार की है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं। उनकी उपज के लिए विशेष बाजार का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। वैश्विक बाजार में इसके निर्यात की योजना है।